

## वस्त्र मंत्रालय

### मंत्रिमंडल के लिए जून, 2019 माह हेतु मासिक सारांश

#### 1. नीतिगत निर्णय

भारत के राजपत्र में प्रकाशित पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पटसन में अनिवार्य प्रयोग के लिए 30 जून, 2019 में समाप्त होने वाले आदेश की वैधता को 30 सितंबर, 2019 तक (या अगले आदेश तक जो भी पहले हो) बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई।

#### 2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

##### I. हथकरघा क्षेत्र :

विदेशी बाजार में हथकरघों को प्रोत्साहित करने के लिए जून, 2019 से 9 जून, 2019 तक 18 प्रतिभागियों के साथ मलेशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले, ग्लोबल इण्डिया फेस्टिवल में भाग लिया गया।

##### II. हस्तशिल्प क्षेत्र :

(अ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लिया/आयोजन किया:

- 8-16 जून, 2019 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एक लाइव प्रदर्शन 'ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल'।
- 19-25 जून, 2019 तक डल्लास मार्केट सेंटर, यूएसए में एक जागरूकता अभियान 'डल्लास हैम्प शॉ'।
- 15-19 जून, 2019 तक एम्सटर्डम, नीदरलैंड में एक प्रदर्शनी 'हैंड मेक इन इंडिया'।
- भारतीय हस्तशिल्प तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार सुविधा को बढ़ावा देने की दृष्टि से 12-24 जून, 2019 तक डीसी (एससी) तथा डीसी (एचएल) बिश्केक, किर्गिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) भारत व किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त प्रदर्शनी, 12 कारीगरों ने इस कार्यक्रम में भाग भी लिया।

(ब) राष्ट्रीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के परिसर में हस्तकला अकादमी स्थापित की गई है।

- III. **कपास:** कपास मौसम 2018-19 के लिए कपास सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक 18.06.2019 को आयोजित की गई। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, वस्त्र उद्योग, कपास व्यापार तथा गिनिंग व प्रैसिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। कपास का परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य-वार क्षेत्र, उत्पादन, आयात, निर्यात तथा कपास की खपत पर भी चर्चा हुई। वर्तमान कपास सीजन 2018-19 के लिए कपास की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र और वर्तमान कपास सीजन 2018-19 के लिए राज्यवार कपास उत्पादन में संशोधन का निर्णय लिया गया।
- III. **विद्युत्करघा क्षेत्र:** विद्युत्करघा के लिए सामूहिक बीमा योजना के तहत जून, 2019 के दौरान कुल 15,89,094 रुपए के भारत सरकार के प्रीमियम के अंशदान से इस योजना के तहत विभिन्न नोडल एजेंसियों ने 9,731 हथकरघा कर्मचारियों को पंजीकृत किया।